डिजिटल होता ग्रामीण भारत

शालू यादव

मुझे याद है जब करीब दस साल पहले मेरे माता-पिता ने मुझे कम्प्यूटर दिलवाया था तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं दिल्ली के उस इलीट क्लब का हिस्सा बन गई थी जिसे एक बटन के क्लिक से दुनिया से जुड़ने का भाग्य प्राप्त है। गर्मियों की छुट्टियों में गांव से जब मेरे चचेरे और ममेरे भाई बहन आते तो कम्प्यूटर देख कर उनकी आंखों में एक ललक सी जाग जाती थी। नई तकनीक का उन्हें इस कद्र शौक था कि छुट्टियां खत्म होने के बाद बुआ को उन्हें जबर्दस्ती वापस ले जाना पड़ता था। आखिर दिल्ली में ही उन्हें ऐसी चीजें देखने को जो मिलती थीं। लेकिन अब समय बदल गया है। आज गांव में रहते हुए भी उनके पास पर्सनल लैपटॉप हैं। हालांकि वहां ब्रॉडबैन्ड इंटरनेट स्पीड कुछ खास नहीं है। ग्रामीण और शहरी भारत के बीच के डिजिटल फासले का जायजा लेने के लिए मैंने भारत के तीन राज्यों का दौरा किया। राजस्थान का चंदौली गांव, केरल का इड्डुकी जिला और मध्य प्रदेश का चंदेरी कस्बा। इन यात्राओं के दौरान जो मैंने देखा और पाया, उससे मेरा पूर्वाग्रह दूर हो गया।

दिल्ली से राजस्थान की ओर बढ़ते हुए सीमा पर पहले तो ऊंची-ऊंची कॉरपोरेट इमारतें दिखाई देती हैं और फिर उसके कुछ ही किलोमीटर बाद खेतों के बीच खड़े कच्चे मकान। गांव की इस मूक सी तस्वीर को देख कर ये नहीं लगता कि यहां इंटरनेट के बारे में किसी को पता भी होगा। लेकिन मैं ही शायद अब भी दस साल पहले की दुनिया में जी रही थी। अलवर के चंदौली गांव में जाकर पता चला कि यहां तो बच्चा-बच्चा इंटरनेट और स्मार्टफोन्स के बारे में जानता है। 10 से 15 साल के बच्चों का आत्मविश्वास भरा कम्प्यूटर और इंटरनेट ज्ञान देख कर मुझे एहसास हुआ कि इस उम्र में इतना आत्मविश्वास तो मुझे शहरों में रह कर भी नहीं मिल पाया था।

भारत की आधी से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और जैसे-जैसे इस आबादी में स्मार्टफोन का इस्तेमाल बढ़ रहा है वैसे ही उनकी उम्मीदें भी बढ़ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गांवों में मुफ्त इंटरनेट पहुंचाने के वायदे को ग्रामीण भारत बहुत गंभीरता से ले रहा है। गांववासी चाहते हैं कि गांवों और शहरों के बीच का डिजिटल भेदभाव अब पूरी तरह से समाप्त होना चाहिए। गांवों में लोगों के बीच इंटरनेट की भूख तो बहुत है लेकिन उस भूख को मिटाने के लिए व्यवस्था पुख्ता नहीं है।

जब गांव के बच्चों को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जी मेल और यू ट्यूब जैसी ऐपलिकेशनों इस्तेमाल करते हुए देखा तो आभास हुआ कि ग्रामीण भारत का भविष्य कितना अलग होने जा रहा है।

वहीं केरल के इड्डुकी जिले के एक छोटे से गांव में एक अनपढ़ आदिवासी ने जब मेरे आइ फोन पर गूगल मैप्स चला कर दिखाया तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि स्मार्टफोन के इस्तेमाल के बारे में लोग खुद ही अपने आप को शिक्षित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के चंदेरी में जहां कुछ सालों पहले बुनकर अपना अस्तित्व खो चुके थे, आज वही बुनकर फेसबुक और व्हाट्सऐप के जरिए ऑनलाइन साड़ियां बेच रहे हैं और खूब मुनाफा कमा रहे हैं। और फिर गांवों के ऐसे नौजवानों से भी मिली जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और इसे एक बेहद मामूली योग्यता मानते हैं।

भारत की आधी से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और जैसे जैसे इस आबादी में स्मार्टफोन का इस्तेमाल बढ़ रहा है वैसे ही उनकी उम्मीदें भी बढ़ रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गांवों में मुफ्त इंटरनेट पहुंचाने के वायदे को ग्रामीण भारत बहुत गंभीरता से ले रहा है। गांववासी चाहते हैं कि गांवों और शहरों के बीच का डिजिटल भेदभाव अब खत्म हो। गांवों में इंटरनेट की भूख तो बहुत है लेकिन उस भूख को मिटाने के लिए व्यवस्था पुख्ता नहीं है। लेकिन फिर एक नौजवान लड़की पूछती है.....इंटरनेट तो आ ही जाएगा गांव में लेकिन गांव वालों की सोच कौन बदलेगा? यहां तो हम लड़कियों के फेसबुक अकाउंट खोलने पर ही बवाल मच जाता है। अब समाज के पढ़े-लिखे वर्ग और सरकारी तंत्र की यह जिम्मेदारी अधिक है कि डिजिटल होते ग्रामीण भारत को वे सभी सुविधाएं भी मिलें जो शहरी इलाकों को उपलब्ध हैं।

The Digital Divide Is Still a Thing

There are parts of the world where internet access is far from being as commoditised as it is in developed regions. According to new figures released by the International Telecommunication Union (ITU), little more than 4 in 10 individuals around the world have internet access in 2015. The different levels of internet adoption in different regions:

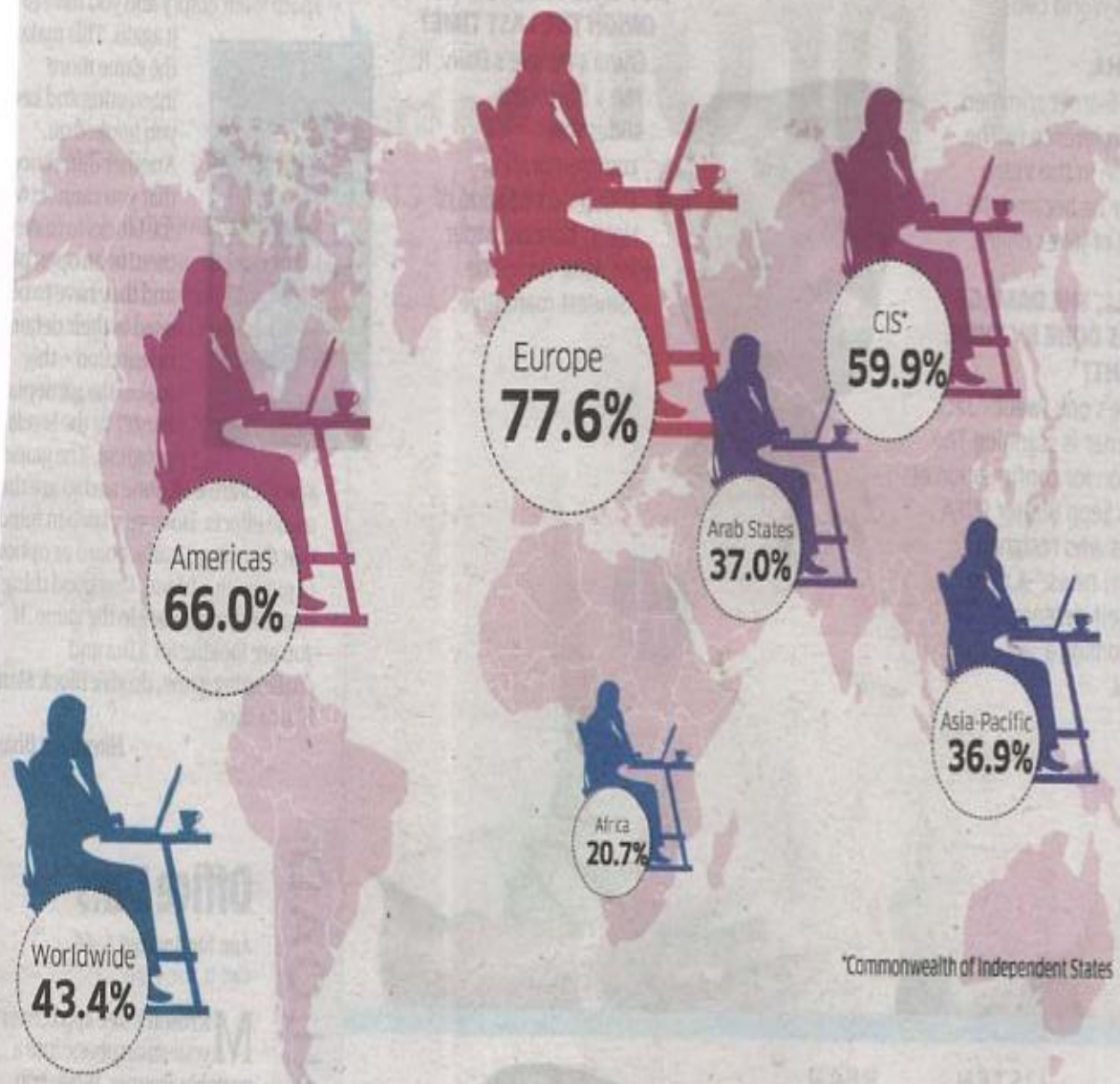

Number of internet users in select countries in 2014

In 2014, nearly 75% (2.1 billion) of all internet users in the world (2.8 billion) live in the top 20 countries

SOURCE: INTERNETLIVESTATS